

पहला कॉलम



सेना में महिला अधिकारियों को दिया गया परमानेंट कमीशन बरकरार रहेगा

महिलाओं के स्थायी सेवा के अधिकारों में अब कोई दखल नहीं
नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (पीसी) देने के अपने पिछले निर्णयों को सही माना है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी सेवा के अधिकारों में अब कोई दखल नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों को पहले से दिया गया परमानेंट कमीशन बरकरार रहेगा, और यह साफ कर दिया कि मौजूदा व्यवस्था में कोई दखल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अधिकारी खास तौर पर शांति सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओएस) और वे लोग जिन्होंने मामले में दखल दिया था जिन्हें कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी भी चरण में सेवा से मुक्त किया गया था, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी कर चुका माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वे पेंशन से जुड़े फायदों की हकदार होंगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन के फायदे तब दिए जाएंगे, लेकिन ये अधिकारी वेतन के किसी भी बकाया के हकदार नहीं रहने वाले हैं। इस फैसले को सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों और सेवा शर्तों को और मजबूत करता है।

आज किसान साल में तीन फसलें ले रहा.....इसलिए उनकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई

केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया पिछली सरकारों में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी
नई दिल्ली। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार का पक्ष रखकर कई अहम बातें कही। उन्होंने दावा किया कि देश में कई किसानों की आय दोगुनी ही नहीं, बल्कि यह कई गुना बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय सिर्फ दोगुनी ही नहीं हुई है बल्कि इसमें दो-तीन गुना तक इजाफा हुआ है और कुछ मामलों में यह आंकड़ा आठ गुना तक बढ़ गया है। इस मूके पर विपक्ष पर निशाना साधकर कहा कि पिछली सरकारों के समय गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। उन्होंने कहा, उस समय न बिजली थी, न पानी और न ही सड़कें थीं। मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर बताया कि पहले वहां किसानों को सिर्फ एक ही फसल मिल पाती थी, क्योंकि बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने कहा, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार सिर्फ बिजली के बिल ही आते थे। उन्होंने बताया कि लेकिन हमारी सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश में किसान साल में तीन-तीन फसलें ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कृषि बजट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कृषि बजट 19,306 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ाकर अब 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। अगर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए, तब कुल बजट 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है।



ईरान जंग पर पीएम मोदी की चेतावनी,

जारी रही लड़ाई तो होंगे गंभीर दुष्परिणाम

राज्यसभा में बोले- आने वाला समय देश की बड़ी परीक्षा, 'टीम इंडिया' की तरह मिलकर करना होगा मुकाबला

-बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट का महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान से जुड़ा संघर्ष, जिसमें अमेरिका और इजरायल शामिल हैं, लंबे समय तक जारी रहा तो इसके गंभीर वैश्विक दुष्परिणाम होंगे। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आने वाला समय भारत के लिए भी एक

बड़ी परीक्षा की घड़ी साबित होगा, जिससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। उच्चसदन को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चेतावनी दी, कि आने वाला समय भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। उन्होंने राज्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को 'टीम इंडिया' की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसा कि कोविड-19 के दौरान किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात का असर भारत के

व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है। विशेष रूप से होमजुज जलडमरूमध्य में जहाजों के फंसने से स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने बताया कि कई भारतीय कूटनयन भी इन जहाजों पर मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित होने से गैस-तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल, गैस और

उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने सात एम्बोवर्ड ग्रुप बनाए हैं, जो सप्लाई चेन, महंगाई और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर निगरानी रखेंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़े कार्रवाई गरीबों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। किसानों को आश्वस्त करते हुए



उन्होंने कहा कि आगामी बुआई सीजन के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठा रही है ताकि कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो।

रक्षामंत्री ने ली बैठक, अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच भारत की रक्षा तैयारियों को परखा

नई दिल्ली।

इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने भी इसका जोरदार जवाब दिया। यह युद्ध अब तक शांत नहीं हुआ। इस युद्ध के टेंशन को देखते हुए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

साथ ही भारत की सैन्य तैयारियों का भी व्यापक आकलन किया। बता दें इस बैठक का मुख्य उद्देश्य युद्ध की वजह से बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच भारत की रक्षा तैयारियों को परखना और किसी भी संभावित चुनौती के लिए रणनीति तय करना था। बता दें इस हार्ड लेवल बैठक में सीमा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, एयर डिफेंस और ऑपरेशनल रेडोनेस जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।



स्थिति से निपटने की क्षमता रखता है। बैठक में सेनाओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत हर स्थिति पर नजर रख रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की और इसके

ईरान ने साफ कहा- बगैर किसी शुल्क के दो भारतीय जहाजों ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज



नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच फंसे भारतीय जहाजों की घर वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। भारी फीस वसूल जाने की खबरों और अनिश्चितता के माहौल के बीच दो महत्वपूर्ण भारतीय जहाज, पाइन गैस और जग वसंत, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक ये जहाज भारतीय तटों पर दस्तक दे सकते हैं। इन जहाजों की आवाजाही को लेकर हाल ही में यह खबरें उठी थीं कि ईरान इनसे गुजरने के बदले भारी शुल्क की मांग कर रहा है। हालांकि, भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। दूतावास ने स्पष्ट किया कि जहाजों से 20 लाख (2 मिलियन) डॉलर की राशि वसूलने की खबरें केवल व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, यह ईरान का आधिकारिक रुख नहीं है। ईरान के अनुसार, इस मार्ग से जहाजों को निकालने के लिए अधिकारियों के साथ पहले से की गई बातचीत और समन्वय ही एकमात्र आधिकारिक रास्ता है। आंकड़ों के अनुसार, एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए। इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,000 टन एलपीजी लदी है, जो भारत में लगभग एक दिन की रसीद गैस की खपत के बराबर है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इन जहाजों की यात्रा शुरू हो चुकी है और आमतौर पर खाड़ी से भारत पहुंचने में इन्हें दो से ढाई दिन का समय लगता है।

जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप, इमरजेंसी चालू

बिलावर। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार द्वारा ढाई दिन का वेतन रोकने के फैसले के खिलाफ मंगलवार और बुधवार को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट फेडरेशन के बिलावर ब्लाक अध्यक्ष करतार सिंह ने बताया कि 24 और 25 मार्च को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनका रोका गया वेतन बहाल नहीं किया गया तो वे रोस्टर ड्यूटी नहीं करेंगे। करतार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को ढाई दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाता था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमटीएस ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोकना किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।

महिलाओं को 2500 प्रतिमाह, बेटियों को 1 लाख

बुजुर्गों को वयोआनंद बजट में महिला-युवा-बुजुर्ग पर फोकस

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 का बजट पेश किया, जिसमें महिला, युवा और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह, लखपति बेटियां योजना के तहत 1 लाख रुपये और बुजुर्गों के लिए वयोआनंद योजना की घोषणा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए महिला, युवा और बुजुर्ग तीनों ही वर्ग पर विशेष फोकस किया। युवा और

महिलाओं के लिए एक ओर जहां 1,03,700 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड बजट में कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं, राजधानी में बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखते हुए वयोआनंद योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए 25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं, महिलाओं से राज्य सरकार ने यह वादा किया है कि इस साल से उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह मिलने लगे। दिल्ली सरकार ने लखपति बेटियां योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली की हर बेटों के जन्म से लेकर



ग्रेजुएशन पूरा करने तक सरकार साथ देगी। ग्रेजुएशन पूरा करने पर बेटों को एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 128 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ युवाओं के विकास पर सरकार की प्राथमिकता है। इन घोषणाओं से दिल्ली के छात्रों को आधुनिक शिक्षा, बेहतर खेल सुविधाएं और करियर के नए अवसर मिलेंगे।

महिला आरक्षण के लिए सरकार ने उदाया बड़ा कदम, अब लोकसभा में 33 प्रतिशत होंगी महिलाएं

नई दिल्ली।

लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का समुचित तरीके से लाभ मिले इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संसद के मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत

आगामी लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। सरकार की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में भारी वृद्धि करना है। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किए जाने का प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि सदन में 273 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

इन नई सीटों में से अधिकांश महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे मौजूदा पुरुष सांसदों की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पिछले पांच दशकों में पहली बार होगा जब सीटों की संख्या में इस स्तर का इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही संसद में बहुमत का आंकड़ा भी बढ़कर 409 हो जाएगा। महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ी बाधा परिसीमन और नई जनगणना को माना जा रहा था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पहले इसे नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार इस प्रावधान को अलग करने पर विचार कर रही है। नई जनगणना में होने वाली देरी को देखते हुए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही नया परिसीमन कराने की योजना बना रही है, ताकि 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों में महिला कोटा प्रभावी रूप से लागू किया

जा सके। इस बदलाव से दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं का भी समाधान होगा, जिन्हें डर था कि जनसंख्या नियंत्रण के सफल प्रयासों के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120,

बिहार की 40 से 60 और केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 होने का अनुमान है। इसी अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में भी वृद्धि की जाएगी। इस विधायी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजनीतिक सरगमों तेज हो गई हैं। सरकार की मंशा 4 अप्रैल को समाप्त हो रहे बजट सत्र में ही इन विधेयकों को पारित कराने की है, जिसके लिए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है।



तकनीक का लोकतंत्रीकरण और सृजन का नया युग

(लेखक - विनोद कुमार सिंह)

- एआई कोशल, नागरिक भागीदारी और सुलभ प्रसारण से बदलता भारत का डिजिटल भविष्य

इंडियन इंस्ट्रूट क्रियेटेवी ट्रेकनॉलॉजी के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय एआई रिकलिंग पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गुगल और यूट्यूब के सहयोग से तैयार यह कार्यक्रम न केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि रचनात्मक उद्योगों के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल भी विकसित करेगा। इससे भारत के युवा वैश्विक डिजिटल कंटेंट बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। दूसरी ओर, एमवाइडब्ल्यूएवीईएस प्लेटफॉर्म उस बदलते भारत का प्रतीक है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज को पहचान दिलाया चाहता है।

वैश्विक क्षितिज पर भारत का डिजिटल परिदृश्य आज जिस तीव्र गति से बदल रहा है, वह केवल तकनीकी प्रगति का शुभ संकेत ही नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का परिचायक भी है। इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के केंद्र में वह सोच है, जो तकनीक को कुछ विशेष वर्गों तक सीमित न रखकर उसे आम जन तक पहुँचाने की वकालत करती है। इसी दृष्टि को साकार करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आरंभ की गई तीन नई पहलें एक नए भारत की डिजिटल आकांक्षाओं को आकार देती दिखाई देती हैं। आज के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीक को सुलभ, सस्ता और सर्वसुलभ बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक डिजिटल क्रांति का भागीदार बन सके। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को दोहराया, जिसमें तकनीक को लोकतांत्रिक बनाने पर विशेष बल दिया गया है। उनके अनुसार, इन पहलों के माध्यम से न केवल तकनीक की पहुँच बढ़ेगी, बल्कि यह आम लोगों के जीवन को सरल और सशक्त भी बनाएगी। मंत्री ने एमवाइडब्ल्यूएवीईएस प्लेटफॉर्म को एक ऐसे सशक्त मंच के रूप में रेखांकित किया, जहाँ देश का हर नागरिक अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त कर सकता है। उन्होंने अपने उद्गार में उल्लेख किया कि आज का भारत केवल कंटेंट का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि वह कंटेंट निर्माण में भी वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने रचनाकारों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र, संस्कृति और परंपराओं की कहानियों को इन मंचों के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाएँ, जिससे भारत की विविधता और समृद्धि को एक नई पहचान मिल सके। राष्ट्रीय ए आई रिकलिंग पहल पर बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कार्यक्रम आनेवाले समय

की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज लगभग 15 हजार युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार किया जाएगा। उनके शब्दों में, 'यह पहल युवाओं को केवल कौशल ही नहीं देगी, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाएगी।' यह कथन इस बात का संकेत है कि सरकार एआई को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख रही है। आज के इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने भी इन पहलों की व्यापकता और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह तीनों पहलें एक साझा नीति दिशा को प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने अपने उद्गार में स्पष्ट किया कि पहली पहल लोगों को सक्षम बनाएगी, दूसरी उन्हें नए अवसर प्रदान करेगी और तीसरी यह सुनिश्चित करेगी कि कंटेंट की पहुँच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो। उनके अनुसार, यह केवल योजनाएँ नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में ठोस कदम हैं। यदि इन उद्गारों को व्यापक संदर्भ में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार की सोच बहुस्तरीय है। एक ओर जहाँ कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अभिव्यक्ति और अवसर के मंच भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, तकनीकी अवरोधों को कम करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन अवसरों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। इंडियन इंस्ट्रूट क्रियेटेवी ट्रेकनॉलॉजी के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय एआई रिकलिंग पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गुगल और यूट्यूब के सहयोग से तैयार यह कार्यक्रम न केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि रचनात्मक उद्योगों के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल भी विकसित करेगा। इससे भारत के युवा वैश्विक डिजिटल कंटेंट बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। दूसरी ओर, एमवाइडब्ल्यूएवीईएस प्लेटफॉर्म उस बदलते भारत का



प्रतीक है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज को पहचान दिलाया चाहता है। यह मंच केवल कंटेंट निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि एक सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद का सेतु भी है। इसके माध्यम से देश के कोने-कोने से उभरती कहानियाँ, विचार और रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ एक साझा मंच पर आ सकेंगी। तीसरी पहल, डीडी फी डिश के लिए इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनिंग और उन्नत प्रोग्राम गाइड की सुविधा, सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन को सरल बनाने का प्रयास है। अब बिना सेट-टॉप बॉक्स के टेलीविजन देख पाना न केवल लागत को कम करेगा, बल्कि तकनीक के उपयोग को भी सहज बनाएगा। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ संसाधनों की कमी के कारण लोग अब तक बेहतर प्रसारण सुविधाओं से वंचित थे। इन सभी प्रयासों के केंद्र में प्रसार भारतीय की भूमिका भी उल्लेखनीय है, जो सार्वजनिक

प्रसारण को आधुनिक और सुलभ बनाने में निरंतर प्रयासरत है। यह स्पष्ट है कि सरकार केवल नई योजनाएँ लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे डिजिटल भविष्य का निर्माण कर रही है, जहाँ अवसर, अभिव्यक्ति और सूचना-तीनों का संतुलित विकास संभव हो। अंततः यह कहा जा सकता है कि आज व्यक्त किए गए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और सचिव के उद्गार केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं हैं, बल्कि वे उस दिशा का संकेत हैं, जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है।

यह दिशा है-सशक्त नागरिक, सुलभ तकनीक और समावेशी विकास की। यदि इन पहलों को प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत न केवल डिजिटल दुनिया का उपभोक्ता होगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। (स्वतंत्र पत्रकार व स्तम्भकार)

गैस की किल्लत या सिस्टम की सुस्ती? वैश्विक संकट में पिसती जनता

(लेखक - दिलीप कुमार पाठक)

दुनिया के मानचित्र पर जब भी किसी देश की सीमाएँ सुलगती हैं, तो उसकी लपटें हजारों मील दूर बैठे एक भारतीय परिवार की रसोई तक पहुँचने में देर नहीं लगाती। आज की वैश्वीकृत दुनिया में सरहदों पर गिरा हर बम हमारी जेब में एक अदृश्य छेद कर देता है। एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ़ सरकारी प्रेस रिलीज और दावे सब कुछ सामान्य होने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ हकीकत यह है कि मोहल्लों की दुकानों और गैस एजेंसियों के बाहर स्टॉक खत्म होने की तस्वीरियाँ लटक रही हैं। सता के गलियारों से जब यह बयान आता है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो यह सुनकर उस कतार में खड़े आम आदमी को सुकून कम और खीझ ज्यादा होती है, जो पिछले कई दिनों से अपने गैस कनेक्शन के रिफिल होने का इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि अगर गैस की कमी नहीं है, तो फिर वह आम आदमी के चूल्हे तक पहुँच क्यों नहीं रही?

राजनीति और कूटनीति की वह बारीक परत है जिसे समझना जरूरी है। सरकार का यह तर्क तकनीकी रूप से सही हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, लेकिन उपलब्धता और पहुँच के बीच की कड़ी बुरी तरह चरमरा गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव ने रसद और परिवहन की कमर तोड़ दी है। जो जहाज पंद्रह दिन में भारत पहुँचते थे, वे अब रास्ता बदलकर आ रहे हैं, जिससे न केवल समय बढ़ गया है बल्कि माल ढुलाई का खर्च भी चालीस प्रतिशत तक ऊपर चला गया है। लेकिन क्या सारा दोष केवल भूगोल और युद्ध पर मढ़ा जा सकता है? हकीकत यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अस्थिर होती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियाँ अपने घाटे को कम करने के लिए आपूर्ति की गति धीमी कर देती हैं। यह एक अलिखित

शांतिग है, जहाँ ऊपर से तो कहा जाता है कि सप्लाय जारी है, लेकिन नीचे वितरकों तक कोटा कम पहुँच रहा है। सरकारी दावों और जमीनी किल्लत के बीच का यह धुंधला क्षेत्र है जहाँ आम आदमी पिस रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिस्टम की पारदर्शिता पर खड़ा होता है। यदि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तो वितरण के स्तर पर यह अचानक गायब कैसे हो जाता है? क्या यह आपूर्ति की बाधा है या फिर संकट की आड़ में छिपी हुई कालाबाजारी का पुराना खेल? जब आपूर्ति स्थूला में अनिश्चितता आती है, तो बिचौलियों और मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, जो कृत्रिम कमी पैदा करके आम आदमी की लाचारी का फायदा उठाते हैं। सरकार को केवल पोर्टल्स पर डेटा अपडेट करने के बजाय उन जमीनी लीकेज को बंद करना होगा, जहाँ से जनता का राशन और हक रिसकर अवैध गोदामों तक पहुँच जाता है। किसी भी आपदा की पहली मार गरीब और मध्यम वर्ग पर ही क्यों पड़ती है, जबकि बड़े कारोबारी इसी संकट को अवसर में तब्दील कर लेते हैं? सरकारी तंत्र की सुस्ती और निगरानी की कमी ने ही आज एक साधारण गैस सिलेंडर को दुर्लभ वस्तु बना दिया है।

सरकार आज बड़े आर्थिक सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की बात कर रही है। लेकिन क्या कोई देश तब तक विकसित कहला सकता है जब उसकी आधी आबादी को आज भी इस बात की चिंता सताए कि कल सुबह चाय बनाने के लिए सिलेंडर में गैस बचेगी या नहीं? यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है; यह उस माँ की जद्दोजहद है जिसे गैस के दाम बढ़ने पर बच्चों के स्कूल की फीस या फल-सब्जियों के बीच चुनाव करना पड़ता है। सरकार अवसर वैश्विक हाकलत हाथ में न होने का तर्क देकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन आपदा प्रबंधन और भविष्य की योजनाएँ केवल कागज़ों पर क्यों मजबूत दिखती हैं? अगर हम जानते थे कि वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, तो देश के भीतर आपूर्ति



तंत्र को इतना लचीला क्यों नहीं बनाया गया कि वह इन झटकों को सह सके? आज देश को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने के कई लक्ष्यों की चर्चा हो रही है, लेकिन पोषण और स्वास्थ्य का सीधा संबंध रसोई से है। अगर ईंधन महंगा होगा या मिलेगा ही नहीं, तो बाकी सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। मध्यम वर्ग आज खुद को एक ऐसे चक्रवर्ष में फंसा हुआ महसूस कर रहा है जहाँ एक तरफ़ उसे सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ़ उसे बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। निष्कर्षतः, सरकार को केवल आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलाना चाहिए। अगर स्टॉक है, तो वह कालाबाजारी में जाने के बजाय सीधे उपभोक्ता तक क्यों नहीं पहुँच रहा? सप्लाय चेन की इस लीकेज को ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि वैश्विक तनाव का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेना। लोकतंत्र में जनता को संसाधनों पर पूरा अधिकार है। जब तक हर घर का चूल्हा बिना किसी डर और डेरी के नहीं जलता, तब तक विकास का हर दावा अधूरा है। (लेखक पत्रकार हैं)

अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है ज्ञान



बुद्धि अच्छी चीज है, पर कोरी बौद्धिकता ही सब कुछ नहीं है। इससे व्यक्ति के जीवन में नीरसता और शुष्कता आती है। ज्ञान अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है, इसलिए यह अपने साथ सरसता लाता है। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए पुस्तकीय अध्ययन की विशेष अपेक्षा नहीं रहती। भगवान महावीर ने कब पढ़ी थी पुस्तकेंट आचार्य भिक्षु, संत तुलसी, संत कबीर अदि जितने ज्ञानवान पुरुष हुए हैं, उनमें कोई भी पंडित नहीं थे। अंतर्दर्शन उनकी ज्ञानमयी चेतना की स्मरणा करता था। इसके आधार पर ही उन्होंने गंभीर तत्वा का विश्लेषण किया। वे यदि पुस्तकों के आधार पर प्रतिबोध देते तो संसार को कोई नया

दृष्टिकोण नहीं दे सकते थे।

एक बात और ज्ञातव्य है। विद्वान बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, पर वे आज तक भी किसी ज्ञानी को पराजित नहीं कर सके। इंद्रभूति महापंडित थे। उनका पांडित्य विश्रुत था। पर वे भगवान महावीर की ज्ञान चेतना का अनुभव करते ही पराभूत हो गए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ज्ञान और बुद्धि की परस्पर कोई तुलना नहीं है।

बुद्धि कुंड का पानी है और ज्ञान कुएं का पानी है। कुंड का पानी जितना है उतना ही रहता है। वर्षा होती है तो पानी थोड़ा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अनकूल सामग्री और पुरुषार्थ का योग

होता है तो बुद्धि बढ़ जाती है। अन्यथा उसके विकास की कोई संभावना नहीं रहती। कुएं से जितना पानी निकाला जाता है, नीचे से और आता रहता है। वह कभी चुकता नहीं है, उसमें नए अनुभव जुड़ते जाते हैं।

बुद्धि आवश्यक है किंतु उसके आधार पर कभी आत्म-दर्शन नहीं हो पाता। आत्म-दर्शन का पथ है ज्ञान। ज्ञान तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक ध्यान का अभ्यास न हो। जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि का उद्घाटन करना है, ज्ञानी बनीका है, उसे प्रेक्षाध्यान साधना का आलंबन स्वीकार करना होगा। ऐसा करके वह ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर सकता है।

विचारमंथन

बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन? चुनाव आयोग और भाजपा जिम्मेदार ?

(लेखक-सनत जैन)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा भाजपा के ऊपर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा, अघोषित रूप से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा गया है। एसआईआर के माध्यम से 63 लाख लाख मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा रहा है। मतदाता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। उन मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश चुनाव आयोग को दिए थे। चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जा रहे हैं। यह स्थिति आपातकाल की तरह है। चुनाव आयोग राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बिना एक तरफा निर्णय ले रहा है। ममता बनर्जी

ने तीखा हमला करते हुए कहा, अब जो भी अच्छा बुरा पश्चिम बंगाल में होगा। उसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। जिस तरह से अधिकारियों को हटाया गया है। उसके कारण पश्चिम बंगाल की सारी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सारे निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था से लेकर हर स्थिति के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक हुई हैं। उससे लगता है, उन्होंने दिल्ली में जो कुछ केजरीवाल सरकार के साथ हुआ था। उसको ध्यान में रखकर सबक लिया है। केजरीवाल सरकार भी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। उप राज्यपाल और चुनाव आयोग के माध्यम से सारे निर्णय लिए जा रहे थे। सारा ठीकरा केजरीवाल के सिर पर फोड़ा गया। जिस तरह से महाभारत में

अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। इसी तरह से केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाकर, वोट काटकर चुनाव आयोग द्वारा पक्षपात कार्यवाही करके सुयोजित तरीके से आम आदमी पार्टी को हराया गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी अपनी बलि नहीं देना चाहती हैं। ऐसा लगता है ममता दीदी कीलाई माली के रोद्र रूप को धारण करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से लड़ने के लिए चुनाव मैदान में अस्त्र-शस्त्र के साथ सबसे बड़ी सुपैट्रिया कह दिया है। इससे उनके आक्रामक तेवर का पता लगता है। ममता बनर्जी पिछले 6 महीनों से एसआईआर की लड़ाई जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। मतदाता सूची

फाइनल हुए बिना चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी तरह से चुनाव भी करा दिए जाएंगे। बिहार में भी ऐसा ही किया गया था। मनमाने तरीके से पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को भाजपा के इशारे पर बदला जा रहा है। चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा धमकाया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सड़क पर आकर लड़ाई लड़कर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। जनता हमेशा आक्रामक तेवर के नेताओं को स्वीकार करती है। यह बात ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाजपा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के लिए ममता का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। चुनाव में धांधली और मनमानी कर पाना आसान नहीं होगा इस

चुनाव में सत्ता तक पहुँचाने के लिए ममता बनर्जी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार दिख रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के लिए चक्रव्यूह ममता बनर्जी ने तैयार किया है। उसके बाद केंद्र सरकार, न्यायपालिका और चुनाव आयोग चक्रव्यूह में रहते हुए साख को बचाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने श्रेष्ठ हसीना के पक्ष में विपक्ष को दबाने और श्रेष्ठ हसीना को जिताने का काम किया था। उसके परिणाम कुछ समय बाद ही बांग्लादेश में देखने को मिले। श्रेष्ठ हसीना को भारत की शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश का असर पश्चिम बंगाल में चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस स्थिति में संवेदनशीलता के साथ निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1,372, निफ्टी 399 अंक उछला।

मुंबई।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। साप्ताहिक के दूसरे ही कारोबारी दिन ये तेजी मध्यमवर्ग में संघर्ष सामना होने की संभावनाओं के कारण आई है। इससे घरेलू बाजार में भी खरीददारी हावी रही।

ऑटो और बैंक शेयरों में भी उछाल आया, जिससे दोनों प्रमुख बेंचमार्क अपने दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुए। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,372.06 अंकों की बढ़त के साथ 74,068.45 पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 399.75 अंक उछलकर 22,912.40 पर था। आज सेंसेक्स एक समय 74,489.39 पर दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जबकि निफ्टी एक समय 23,057.30 तक पहुंच गया। व्यापक बाजारों में बेंचमार्क

सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप में 2.60 फीसदी की तेजी रही जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.63 फीसदी की बढ़त रही।

ऑटो सेक्टर में 2.43 प्रतिशत की बढ़त दर्ज रही जबकि निफ्टी मीडिया में 3.45 प्रतिशत की तेजी आई। निफ्टी बैंक सेक्टर 2.27 फीसदी की तेजी रही।

निफ्टी आईटी में 1.72 फीसदी जबकि निफ्टी एफएमसीजी में 1.25 फीसदी की तेजी आई। आज इंडिया और एलएंडटी के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.49 फीसदी और 5.17 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद बजाज फाइनेंस, इटरनल, एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। कोल इंडिया, पावरग्रिड, सन फार्मा और सिप्ला के शेयरों में गिरावट आई। बाजार में आई तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में 7.74 लाख करोड़ रुपए की

बढ़त आई। इससे गत दिवस के 15.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 422.85 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार एक ही दिन में निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इससे पहले आज सुबह बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और अमेरिका तथा ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों ने निवेशकों के मनोबल को बढ़ाया।

सेंसेक्स 500 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 74,212.47 पर खुला। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 1067.47 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 73,763.86 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 भी मजबूत शुरुआत के साथ 22,878 पर खुला।

बाजार में इस तेजी के पीछे प्रमुख कारण अमेरिका और ईरान



के बीच संभावित बातचीत की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा था कि दोनों देशों के बीच

सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव का समाधान निकल सकता है। विश्वोपज्ञों के अनुसार वैश्विक

स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसका असर बाजार में तेजी के रूप में दिखता है।

भारतीय रेलवे ने किए बड़े बदलाव, टिकट रिफंड और अपग्रेड नियम हुए सरल

8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा

नई दिल्ली।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टिकट नीतियों में सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब टिकट कैसिलेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनानी चाहिए। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर केवल 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। तीन दिन (72 घंटे) पहले रद्द करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि 25 फीसदी कटौती के साथ सिर्फ 75 फीसदी राशि लौटाई जाएगी। यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि अब ऑफलाइन टिकट रद्द कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है जहां टिकट खरीदी गई थी। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर रिफंड लिया जा सकेगा। इससे यात्रियों की भागदौड़ कम होगी और सुविधा बढ़ेगी। रेलवे ने यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अब यात्री ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक कोच या क्लास बदल सकते हैं, यानी स्लीपर से एसी में अपग्रेड संभव होगा। इसके अलावा, अगर कोई यात्री तय स्टेशन के बजाय आगे के किसी स्टेशन से ट्रेन फकड़ना चाहता है, तो मोबाइल ऐप के जरिए बोर्डिंग पॉइंट बदलना अब आसान होगा। इन बदलावों का मकसद यात्रियों को अधिक लचीलापन देना और सीट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।



एचडीएफसी बैंक में चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बाहरी जांच शुरू

नई दिल्ली।

देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी में अचानक बदलाव ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहस छेड़ दी है। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 से अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने इस्तीफे में बैंक के भीतर कुछ प्रथाओं और गतिविधियों का हवाला दिया, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे के पीछे कोई अन्य महत्वपूर्ण वजन नहीं है। बैंक ने उनके इस्तीफे में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए बाहरी लॉ फर्मस नियुक्त की हैं। बैंक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम पूरी तरह प्रोपेक्टिव है और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यपरक समीक्षा करना है। बैंक दशकों से अपनाए गए उच्चतम गवर्नेंस मानकों के अनुरूप खुद को परखता रहा है और यह पहल उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण, कर्ज और ब्याज बोझ बढ़ा

वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 41,173 करोड़ रुपये कर्ज लिया

शिमला।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 41,173 करोड़ रुपये कर्ज लिया और 32,004 करोड़ रुपये चुकाए। इस तरह कुल ऋण देनदारी 2025-26 में 1,03,994 करोड़ रुपये रही, जो 2026-27 में बढ़कर 1,12,319 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पिछले तीन वर्षों में कर्ज लगातार बढ़ता रहा- 2022-23 में 76,681 करोड़, 2023-24 में 85,295 करोड़ और 2024-25 में 93,625 करोड़। ब्याज भुगतान 2024-25 में 6,261 करोड़ था, जो 2025-26 में 6,693 करोड़ और 2026-27 में 7,271 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। वेतन, पेंशन, कर्ज और ब्याज जैसी प्रतिबद्धताओं पर कुल बजट का लगभग 80 फीसदी खर्च होता है। सब्सिडी घटाकर 2026-27 में 859 करोड़ रुपये, 2027-28 में 911 करोड़ और 2028-29 में 965 करोड़ रुपये करने का अनुमान है। इससे पूंजीगत कार्यों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए केवल 20 फीसदी बजट बचता है।



एसीएमई सोलर ने राजस्थान में 155 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की

नई दिल्ली।

एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने अपनी अनुपंगी कंपनियों के माध्यम से राजस्थान में 155 मेगावाट /470.25 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) लॉन्च की है। अब कंपनी की कुल चालू बीईएसएस क्षमता 297.67 मेगावाट/951.74 मेगावाट-घंटा हो गई है। ये बैटरियां मौजूदा अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली से जुड़ी हैं और मुक्त बाजार के आधार पर संचालित होंगी। कम मांग के समय चार्ज और उच्च मांग में ऊर्जा निर्वहन से अतिरिक्त राजस्व होगा। विशेष इकाई के तहत कुल बीईएसएस क्षमता 835 मेगावाट/3,114.64 मेगावाट-घंटा है। एसीएमई सोलर का कुल नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 8,071 मेगावाट है, जिसमें सौर, पवन, भंडारण और मिश्रित समाधान शामिल हैं। यह कदम न केवल ऊर्जा संतुलन बढ़ाएगा बल्कि ग्रिड की स्थिरता में भी योगदान देगा।

केपीआईएल को टीएंडडी कारोबार में 4,439 करोड़ के ठेके मिले

नई दिल्ली।

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (केपीआईएल) और उसकी अनुपंगी कंपनियों को पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में करीब 4,439 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं। इनमें अफ्रीका में 400 किलोवाट पारेषण लाइन और सबस्टेशन, भारत में पारेषण लाइन परियोजनाएं और स्वीडन में एक सबस्टेशन परियोजना शामिल हैं। कंपनी के एक वे रिष्ठ अंधे थिकारी ने कहा कि टीएंडडी कारोबार कंपनी को अपनी मजबूत बाजार स्थिति और एकीकृत क्षमताओं का लाभ उठाकर विश्वस्तरीय इंपीसी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि नए ठेकों के साथ कंपनी ने 26,000 करोड़ रुपये के वार्षिक ऑर्डर लक्ष्य को पार कर लिया है। केपीआईएल मुख्यतः बिजली पारेषण और वितरण, भवन एवं कारखाने, जल आपूर्ति और सिंचाई, रेलवे, तेल एवं गैस पाइपलाइन, शहरी परिवहन, राजमार्ग और हवाई अड्डों में कार्य करती है। यह कंपनी इंपीसी क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है और अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के जरिए उद्योग में मजबूत स्थिति बनाए रखती है।



राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

जयपुर।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को पेट्रोल 104.72 रुपये और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल का दायरा 104.72 से 105.21 रुपये और डीजल का 90.21 से 90.65 रुपये के बीच रहा। राजधानी में स्थिरता के बावजूद राज्य के अन्य जिलों में कीमतों में हल्की बढ़त और गिरावट देखी गई। अजमेर में पेट्रोल 0.17 रुपये बढ़कर 104.53 रुपये और अलवर में 0.36 रुपये घटकर 104.83 रुपये प्रति लीटर रही। बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दाम लगभग स्थिर 106.20 से 106.21 रुपये के बीच हैं। नागौर में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, पेट्रोल 1.01 रुपये बढ़कर 106.29 रुपये प्रति लीटर हुआ। दौसा और कोटा में क्रमशः 0.70 और 0.67 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, डींग में 0.69 रुपये और जोधपुर में 0.34 रुपये की गिरावट हुई। झुंझुनूं, चूरू और सिरोही में भी कीमतें कम हुईं। डीजल की कीमत जयपुर में स्थिर बनी रही, लेकिन अन्य जिलों में



बदलाव नजर आया। अजमेर में 0.16 रुपये की बढ़त हुई और अलवर में 0.32 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। नागौर में 0.93 रुपये की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई। दौसा और कोटा में क्रमशः 0.63 और 0.61 रुपये बढ़े, जबकि डींग और जोधपुर में दाम घटकर क्रमशः 89.75 और 90.00 रुपये पर आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर-रुपये का विनिमय दर और टैक्स स्ट्रक्चर ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को योजना रेट्स चेक करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मामूली बदलाव हमेशा संभव हैं।

जीएसपी क्रॉप साइंस का शेयर चार प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचीबद्ध



नई दिल्ली।

कृषि रसायन कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड का शेयर मंगलवार को अपने निर्गम मूल्य 320 रुपए के मुकाबले 3.84 रुपए की बढ़त के साथ बीएसई पर 332.30 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर में और तेजी आई और यह 362.30 रुपए तक पहुंच गया, जो लगभग 13.21 फीसदी की बढ़त दर्शाता है। कंपनी का 400 करोड़ रुपये का आईपीओ 304-320 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में आया था। अंतिम बोली के दिन आईपीओ को 1.61 गुना

अभिदान मिला, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंजाज लगाया जा सकता है। कंपनी ने आईपीओ से जुटाई गई 170 करोड़ रुपए की राशि का एक हिस्सा ऋण भुगतान के लिए और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखने की योजना बनाई है। जीएसपी क्रॉप साइंस 39 वर्षों से अधिक समय से भारत में कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फूटदनाशक और पादप रोग निरोधक विकास एवं विनिर्माण में सक्रिय है। यह एक अनुसंधान-केंद्रित कृषि रसायन कंपनी के रूप में जानी जाती है।

भारत का ऑयल और गैस सेक्टर पश्चिम एशिया तनाव से प्रभावित

देश में गैस सप्लाई में लगभग 45-47 एमएमएससीएमडी की गिरावट

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत का ऑयल और गैस सेक्टर भारी दबाव में है।

एटीक स्टॉक ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार इस संकट के कारण देश में गैस सप्लाई में लगभग 45-47 एमएमएससीएमडी की कमी हुई है। सबसे अधिक असर गैल पर पड़ा है, जबकि ओएनजीसी को इसका लाभ मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएनजीसी के नए प्रोजेक्ट्स जैसे दमन और केजी बेसिन में उत्पादन बढ़ने वाला है। इसके साथ ही कच्चे तेल

टाटा पावर ने जीयूवीएनएल के साथ अनुपूरक बिजली खरीद समझौते किए

- संयंत्र संचालन अस्थायी रूप से किया गया निलंबित

नई दिल्ली।

टाटा पावर की इकाई कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ मूंदड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए अनुपूरक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह कदम मूंदड़ा स्थित संयंत्र की इकाइयों के अस्थायी निलंबन के कारण हुआ नुकसान कम करने के लिए उठाया गया है। 2 जुलाई 2025 को संयंत्र की सभी पांच इकाइयों (प्रत्येक 800 मेगावाट) का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। बंद रहने के

कारण कंपनी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी ने पहले ही शेयर बाजार को सूचित किया था कि गुजरात मंत्रिमंडल ने इस अनुपूरक पीपीए को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी किया जा चुका है। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते से सीजीपीएल को संयंत्र बंद रहने के दौरान भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। टाटा पावर की योजना इसी तरह के अनुपूरक समझौते अन्य राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ करने की भी है। मूंदड़ा यूएमपीपी कच्छ, गुजरात में स्थित एक 4,000 मेगावाट का



कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। इसमें पांच इकाइयां हैं, प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट। यह संयंत्र गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बिजली आपूर्ति करता है।

कंपनी का कहना है कि अनुपूरक पीपीए से संयंत्र के अस्थायी बंद होने से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और यह बिजली आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोना-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते कूटनीतिक तनाव और ईरान-अमेरिका के बीच जुबानी टकराव ने सोना और चांदी के निवेशकों को हैरान कर दिया है। मंगलवार सुबह मल्टी कम्पोजिट एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर हॉर्मज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंकाओं और ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की खबरों ने बाजार को हिलाकर रख दिया। अप्रैल वायदा सोना 1,36,945 रुपये प्रति 10 ग्राम

पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 2,315 रुपये कम है। वहीं चांदी का मई अनुबंध 2,15,765 रुपये प्रति किलोग्राम पर फिसल गया, यानी 9,569 रुपये की गिरावट। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,050, 22 कैरेट 12,880 और 18 कैरेट 10,541 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें लगभग 4,300 डॉलर प्रति औंस पर संघर्ष कर रही हैं। इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतें हैं। सोमवार को जब ट्रंप ने बातचीत का संकेत दिया था, तब कीमतें थोड़ी उछली



थीं, लेकिन अब अनिश्चितता और भू-राजनीतिक दबाव ने फिर से कीमतों को नीचे धकेल दिया है। मार्च में सोना अपने शिखर से लगभग 25 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें

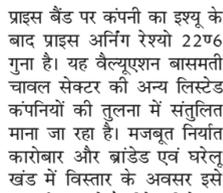
और संभावित ब्याज दरों में वृद्धि निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत देती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस समय बाजार में छोटे उतार-चढ़ाव पर जल्दबाजी में निवेश निर्णय न लें।

बासमती चावल निर्यातक कंपनी एक्सपोर्ट्स का आईपीओ खुला

नई दिल्ली।

हरियाणा स्थित बासमती चावल निर्यातक कंपनी अमीर चंद जागदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार को खुल गया। यह पेशकश पूरी तरह से नए इंडिटी शेयरों की होगी और इसमें कोई ऑफर फंड सेल; ओएफएसडू शामिल नहीं है। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 201 से 212 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अपर प्राइस

बैंड पर कुल इश्यू साइज 400 करोड़ रुपए का है। नॉन-लिस्टेड शेयर मंगलवार को ग्रे मार्केट में 219 रुपए पर कारोबार कर रहे थे जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 212 रुपए के मुकाबले 3 फीसदी प्रीमियम दर्शाता है। इसका संकेत है कि निवेशकों में आईपीओ को लेकर सकारात्मक भावना है। ब्रोकरेज हाउस एंजल वन ने इस आईपीओ को सप्सक्राइब फंड लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के अनुसार अपर



मॉडल सुरक्षित है। ब्रोकरेज ने कहा कि अब इसमें जोखिम कम है और सुधार की संभावना है। आईजीएल की बिजनी फिनाहल ठीक चल रही है, लेकिन अनेक वामले समय में



प्राइस बैंड पर कंपनी का इश्यू के बाद प्राइस अनिर्गम रेश्यो 2296 गुना है। यह वैल्यूएशन बासमती चावल सेक्टर की अन्य लिस्टेड कंपनियों की तुलना में संतुलित माना जा रहा है। मजबूत निर्यात कारोबार और ब्रांडेड एवं घरेलू खंड में विस्तार के अवसर इसे आकर्षक बनाते हैं। रिटेल निवेशक अधिकतम 70 शेयर प्रति आवेदन खरीद सकते हैं। जिससे 1 लॉट की कीमत 14ए840 रुपए होगी। कुल आईपीओ का 50 फीसदी



मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। सस्ती गैस की सप्लाई धीरे-धीरे कम हो रही है, जिससे अगले 2-3 साल में मार्जिन प्रभावित हो सकता है।

मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। सस्ती गैस की सप्लाई धीरे-धीरे कम हो रही है, जिससे अगले 2-3 साल में मार्जिन प्रभावित हो सकता है।



लॉग टर्म कोर्स की बजाय रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज के युवा

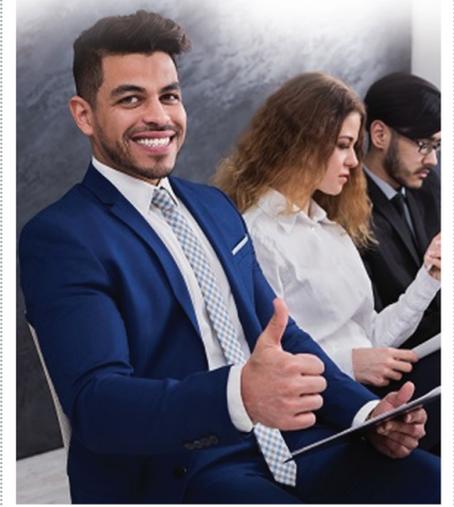
नौकरी तलाश करने वालों के लिए ये जो अनिष्ट ठहराया आया है, संभवतः उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जब वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी प्रेक्षित विशेषज्ञता को बढ़ा सकते हैं।

एक ऑनलाइन शैक्षिक कंपनी, टेलेंटेज और मार्केट रिसर्च एजेंसी के एक ताजा सर्वे के अनुसार भविष्य में लंबी अवधि के करियर की योजना बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि विकास की गति जॉब मार्केट में बढ़ रही है और युवाओं को लगातार समय की मांग के मुताबिक खुद को ऐसे परिवेश में ढालना बेहद जरूरी होगा। वहीं इससे पहले किये गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक आधा से ज्यादा नौकरी तलाश करने वालों ने लंबी अवधि के करियर के उचित अवसर और विकास के लिए अपने कौशल को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। नौकरी तलाश करने वालों के लिए ये जो अनिष्ट

ठहराया आया है, संभवतः उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जब वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी प्रेक्षित विशेषज्ञता को बढ़ा सकते हैं। डेटा साइंस और एनालिटिक्स कोर्स (22 प्रतिशत), इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग (20 प्रतिशत), और वित्त और जोखिम प्रबंधन (16 प्रतिशत) शीर्ष पाठ्यक्रमों में से थे जो नौकरी ढूढ़ने वालों द्वारा चुने गए थे।

गेजिंग इन टू द फ्यूचर

यंग इंडिया, देयर एस्पिरेशंस एंड करियर चॉइस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अल्पकालिक पेशेवर योजना ही एक सही रास्ता है। उत्तरदाताओं ने कहा कि वे तेजी से एक 'नौकरी' के बारे में सोचेंगे और 'करियर' नहीं, क्योंकि उनके आसपास की चीजें तेजी से बदल रही हैं और वे अगले पांच वर्षों में भी ऐसे जीवन करियर की कल्पना नहीं कर सकते हैं जब बहुत सारे वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के होते हुए भी शायद ही कुछ ऐसे होंगे जो एक उचित परिपेक्ष्य में, अनुकूल और लाभप्रद रोजगार दे सकेंगे। टेलेंटेज ने 20,000 छात्रों में से ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान की है जिन्होंने इस संस्था में पिछले वर्ष नामांकन किया था, उनमें से 60 उत्तरदाताओं ने इस सर्वे में भाग लेने के लिए फाइनल कट दिया है। सर्वेक्षण पर आधारित यह अध्ययन लगभग पांच वर्षों तक किया गया, जिसमें से मानव संसाधन प्रमुखों, सीएक्सओ, करियर काउंसलर और समाजशास्त्रियों के उत्कृष्ट विचारों को संज्ञान में लिया गया, ताकि इस उभरते हुए झुकाव की विस्तृत तस्वीर सामने आ सके और उम्मीदवारों को सही मार्गदर्शन मिल सके। टेलेंटेज के आदित्य मालिक ने एक बिजनेस समाचार पत्र में दिए गए एक वक्तव्य में बताया कि 29 साल की औसत आयु के साथ भारत 2026 तक दुनिया का सबसे युवा देश होगा। उन्होंने बताया कि वो युवा भारतीयों के विचारों को, उनके करियर के विकल्पों की संभावनाओं को और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में समझना चाहते थे। अध्ययन में पाया गया कि डिग्रियों का कम्पित अधिग्रहण करियर का एक नया मापदंड होगा, जैसा कि उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें क्रियाशील व व्यावहारिक तजुबों से सीखना होगा और जरूरत पड़ने पर और अधिक डिग्री हासिल करनी होगी। विशेषज्ञों ने इस सर्वेक्षण पर विचार विमर्श किया और पाया कि शिक्षा सिर्फ एक बार का मामला नहीं होगा बल्कि एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें युवा जैसे जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, डिग्रियां हासिल करते रहेंगे। आदित्य मालिक ने आगे बताया कि कॉर्पोरेट दुनिया के साथ बढ़ती निराशा युवाओं के जूनून को काम में परिवर्तित करने में उन्हें आगे ले जाएगी। लौक से हटकर बढ़ते हुए पाठ्यक्रमों ने नए करियर को पंख दे दिए हैं। और आज के युवा भी शायद इसे ही ज्यादा महत्त्व दे रहे हैं और अपना रुझान भी इसी पर केंद्रित कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार के लिए आज एक बहुत बड़ा स्कोप खुल गया है, यह स्वीकार करते हुए कि वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि यह कितना आकर्षक होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक युवा हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शर्टटर्म का कोई मनचाहा कोर्स आपको सही दिशा में ले जायेगा या फिर कोई लॉन्गटर्म वाला कोर्स।



एक जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों अर्थात प्राचीन जीवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी या प्रागैतिहासिक जीवन पर पिछले जीवन की पड़ताल की जा सके। यह छोटे बैक्टिरिया से लेकर विशालकाय डायनासोर तक हैं, ये जीवाश्म एक अरब वर्ष पुराने भी हो सकते हैं।

पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लाखों-करोड़ों साल पहले ही हो गई है। ऐसे कई जीव व जानवर हैं, जो सालों पूर्व धरती पर मौजूद थे, लेकिन अब वह विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन उनके जीवाश्म की मदद से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन को ही पेलियोन्टोलॉजी कहा जाता है। यह जीवाश्मों के अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी पर पिछले जीवन की जांच है। जीवाश्म पौधों, जानवरों, कवक, बैक्टिरिया और अन्य एकल-कोशिका वाले जीवित जीवों के अवशेष या निशान हैं जो भूवैज्ञानिक अतीत में रहते थे और पृथ्वी की क्रस्ट में संरक्षित हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि पेलियोन्टोलॉजिस्ट सिर्फ डायनासोर का अध्ययन करते हैं, जबकि यह सच नहीं है। बल्कि यह जीवाश्मों की मदद से पृथ्वी पर जीवित चीजों की पूरी प्रजातियों का अध्ययन है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं करियर

क्या होता है काम

एक जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों अर्थात प्राचीन जीवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी या प्रागैतिहासिक जीवन पर पिछले जीवन की पड़ताल की जा सके। यह छोटे बैक्टिरिया से लेकर विशालकाय डायनासोर तक हैं, ये जीवाश्म एक अरब वर्ष पुराने भी हो सकते हैं। वे प्रागैतिहासिक जीवन रूपों और जीवाश्मों की परीक्षा के माध्यम से पौधे और पशु जीवन के विकास पर शोध करते हैं। वे विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानने के लिए जानवरों की हड्डियां, गोलें और कास्ट का उपयोग



वर्तमान समय में, छात्रों के लिए संभावनाओं का एक खुला आसमान है, जहां पर वह विवरण करके एक सुखद व सफल भविष्य बना सकते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है लेक्सोग्राफी। हो सकता है कि आपके लिए यह शब्द नया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि शब्दकोश प्रारूप में 'शब्द' लिखने की कला को लेक्सोग्राफी कहते हैं। लैंग्वेज स्टडी के इतिहास में इसका एक अहम स्थान है। जिसमें शब्दकोश निर्माण के दौरान इतिहास, थ्योरी, मैथडोलॉजी और टाइपोलॉजी शामिल हैं। अगर आप भी अलग-अलग भाषाओं के साथ अपना भविष्य देखते हैं तो आप लेक्सोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर-

क्या होता है काम

लेक्सोग्राफर एक प्रोफेशनल भाषाविद होते हैं, जो डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया व अन्य रेफरेंस टेक्स्ट जैसे लॉ ऑफ मेडिकल डिक्शनरी बनाने के लिए रिसर्च, लेखन, संकलन व संपादन करते हैं। आमतौर पर, लेक्सोग्राफी को दो शाखाओं में

जीवाश्म विज्ञानी के रूप में तलाशों रोजगार की संभावनाएं

करते हैं। साथ ही वह जीवाश्मों का पता लगाने और जीवाश्मों के बारे में प्रासंगिक तथ्यों की पहचान करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनके कार्यक्षेत्र में जीवाश्मों का पता लगाना और उनकी खुदाई करना, निष्कर्षों की पहचान, अनुसंधान और उन्हें साझाकरण करना शामिल है।

पर्सनल स्किल्स

पेलियोन्टोलॉजिस्ट को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सांख्यिकीय विश्लेषण में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा उसमें मौखिक और लिखित संचार कौशल भी होने चाहिए, क्योंकि उन्हें पेशेवरों की एक टीम के साथ काम करना होता है। पेलियोन्टोलॉजिस्ट के पास उच्च जिज्ञासा स्तर और इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। उन्हें तार्किक और गंभीर रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासु और अत्यंत विश्लेषणात्मक होना चाहिए, और एकत्रित डेटा या जानकारी से निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। चूंकि जीवाश्म विज्ञान एक कठिन काम है, जिसमें जीवाश्मों को खोजने और खुदाई करने के लिए बहुत से बाहरी काम करने की आवश्यकता होती है, एक ड्यूटि व्यक्ति को धैर्यपूर्ण होना चाहिए।

योग्यता

पेलियोन्टोलॉजी एक विज्ञान से संबंधित लेकिन व्यापक क्षेत्र है। इसलिए एक जीवाश्म विज्ञानी को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और

भूविज्ञान को जानना आवश्यक है। जीवाश्म विज्ञान में अधिकांश प्रवेश स्तर के पदों के लिए भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान में मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है। वहीं रिसर्च और कॉलेज टीचिंग के लिए पीएचडी होना आवश्यक है। कई भाषाओं का ज्ञान इस क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।

रोजगार की संभावनाएं

एक पेलियोन्टोलॉजिस्ट के रूप में आप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान, संग्रहालयों, या राज्य और संघीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, प्रयोगशालाओं आदि में काम कर सकते हैं। जीवाश्म विज्ञानी सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

आमदनी

एक जीवाश्म विज्ञानी की आमदनी उनके शिक्षा के स्तर, अनुभव व जहां पर वे काम करते हैं, उस पर निर्भर करती है। निजी क्षेत्र में आपकी योग्यता व अनुभव के आधार पर अच्छा वेतन मिलता है। शुरुआती रूप में एक जीवाश्म विज्ञानी 15000 से 25000 रूपए प्रतिमाह आसानी से कमा सकता है। इसके बाद आपके अनुभव के आधार पर आमदनी बढ़ती जाती है।

प्रमुख संस्थान

भारत में केवल एक संस्थान जीवाश्म विज्ञान में एक पाठ्यक्रम प्रदान करता है और यह हैदराबाद के बंडलागुडा में स्थित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है।

एक लेक्सोग्राफर को संबंधित भाषा का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी पर उनकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही विभिन्न भाषाओं को जानने की जिज्ञासा, पढ़ने की आदत, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल, टीम वर्क और लिखित संचार कौशल, प्रभावी समय प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल हैं।

पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करते हैं। वह अपना करियर असिसटेंट एडिटर या फिर जूनियर एडिटीरियल असिसटेंट के तौर पर शुरू कर सकते हैं। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद आप बतौर लेक्सोग्राफर काम कर सकते हैं। आमदनी - यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें लोग सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। एक पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाले लेक्सोग्राफर 15000 से 20000 रूपए प्रतिमाह कमा सकते हैं। वैसे कई लेक्सोग्राफर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं और इस तरह वह हर प्रोजेक्ट के लिए चार्ज करते हैं।

प्रमुख संस्थान

- डेक्कन संस्थान, पुणे
- पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
- मद्रास विश्वविद्यालय केरल विश्वविद्यालय, केरल
- भारथिअर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर

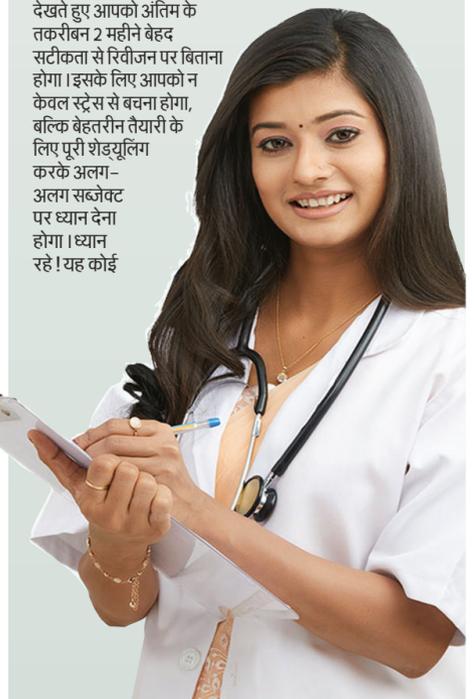


डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है नीट परीक्षा ऐसे करें तैयारी

नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह परीक्षा देशभर में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है। 12वीं के बाद अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित एमबीबीएस अथवा बीडीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप को इस नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बता दें कि नेशनल टैलेंट एजेंसी यानी एनटीए द्वारा इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबजेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए। जान लें कि अगर आपने 12वीं की पढ़ाई ठीक ढंग से की है, खासकर बायोलॉजी, फिजिक्स व केमिस्ट्री में, तो आप इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली एकमात्र मेडिकल परीक्षा है। अतः कंपटीशन बेहद कठोर होता है। अतः मुश्किल तो होगी, किन्तु यह नामुमकिन कतई नहीं है। परीक्षा के माध्यम की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में इसके प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ऑनलाइन इसकी काउंसलिंग होती है और नेशनल लेवल के अलावा स्टेट लेवल पर भी इसकी काउंसलिंग केंद्रों की जाती है। इसमें अलग-अलग टैगरेटरी के हिसाब से सीटों को आवंटित किया जाता है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी दूसरी कई जानकारीयों आपको मिल जाएंगी। यहां तक कि आप मॉक टेस्ट का पेपर भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। करियर एक्सपर्ट्स तैयारी के लिए सलाह देते हैं कि आपको काफी पहले से इस पर ध्यान देना होता है, किंतु जिस स्तर का टफ एग्जामिनेशन होता है, उसे देखते हुए आपको अंतिम के तकरीबन 2 महीने बेहद सटीकता से रिवीजन पर बिताना होगा। इसके लिए आपको न केवल स्ट्रैस से बचना होगा, बल्कि बेहतरीन तैयारी के लिए पूरी शेड्यूलिंग करके अलग-अलग सजेक्ट पर ध्यान देना होगा। ध्यान रहे! यह कोई

नीट परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबजेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए।

साधारण एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए आप भिन्न एक्सपर्ट्स से मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करें। इसमें पिछले वर्ष के टॉपर्स का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, जिसे आपकी पढ़ना-सुनना चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। किन्तु अंत में आपको डिस्प्लिन और बेहतरीन रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट पेपर अधिक से अधिक बार सॉल्व करना आप के लिए सबसे मददगार साबित हो सकता है। कफिहेंसिव रिवीजन इसमें काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए आपको एनसीआरटी बुक्स का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अंत में आपको संपूर्ण सिलेबस पर ध्यान देना होता है और सिलेबेटव टॉपिक्स को स्टडी करने से बचना है। आपको सम्पूर्ण कोर्स के अधिक से अधिक हिस्सों को, कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत ही आपको इसमें इंसिफ्ट परिणाम दे सकती है।



तमिलनाडु में फिर बनेगी डीएमके सरकार, प्री-पोल सर्वे में 180 सीटें जीतने का दावा

सीएम के लिए स्टालिन लोगों की पसंद, टीवीके चीफ विजय परेम्बूर से हार सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्री-पोल सर्वे जारी किया गया है। इसमें डीएमके सरकार फिर से बनने का दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक डीएमके गठबंधन 44.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 234 में से 180 सीटें जीत सकता है। विपक्षी एआईएडीएमके गठबंधन को 54 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसका वोट शेयर करीब 38.5 फीसदी बताया है। तमिलनाडु वेत्री कझम (टीवीके) को 9.7 फीसदी वोट मिल सकता है।

सर्वे में कहा गया है कि टीवीके चीफ अभिनेता विजय परेम्बूर सीट से चुनाव हार सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सीएम एमके स्टालिन का मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव है। सर्वे में शामिल 60 फीसदी से ज्यादा महिलाएं 5000 सहायता योजना के कारण डीएमके को समर्थन दे सकती हैं। सर्वे 7 फरवरी से 12 मार्च के बीच किया गया था। इसमें कुल 1,01,643 लोगों ने अपनी राय दी। इससे पहले एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए ने सोमवार को सीट बंटवारा फाइनल कर दिया।

इसके तहत एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को 27 सीटें मिली हैं। पीएमके को 18 और एएमएमके को 11 सीटें दी गई हैं। वहीं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारा हो गया है। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डीएमके को बाकी 14 सीटें दी गई हैं। डीएमके अपनी हिस्सेदारी में से इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भी सीटें देगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थीं। वहीं डीएमके ने 13 सीटों पर

चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थीं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने 15 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 13 सीटों पर सीपीआई (एम) के उम्मीदवार हैं, जबकि 2 सीटों पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) के उम्मीदवार शामिल हैं। असम में बीजेपी-नेतृत्व वाला गठबंधन मंगलवार को से औपचारिक रूप से अपना चुनाव अभियान शुरू करेगा। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेता रैलियों और बैठकों का नेतृत्व



करेंगे। सरमा ने कहा कि राज्य में पीएम मोदी की करीब 4 से 6 रैलियां और गृह मंत्री की करीब 8 रैलियां होंगी। मोदी और शाह के

अलावा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और अन्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय नेता भी कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे।

दिल्ली विधानसभा, मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षाकर्मियों ने ली तलाशी

स्पीकर और दिल्ली सीएम को मिले ई-मेल, धमकियों के बावजूद दिल्ली का बजट पेश



नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह 7:49 बजे स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता को ईमेल आया और 7:28 बजे विधानसभा को ईमेल आया। ईमेल में एलजी तरनजीत संधू, पीएम मोदी, गुहमंत्र अमित शाह, विदेश मिनिस्टर जयशंकर और साथ में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम लिखा। धमकी मिलने के बाद सुरक्षाकर्मियों विधानसभा स्पीकर के रूम में जांच करने पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को भी धमकी से भरा ईमेल आया था। दिल्ली असेंबली में बम की धमकी वाले मेल के बाद स्निफर डॉग स्कान वहां पहुंचा और जांच की। बम की धमकी वाला मेल मिलने पर बीजेपी विधायक अनिल गौयल ने कहा कि यह एक धोखा था। सब कुछ सुरक्षित है, हम बैठक के लिए जा रहे हैं। धमकियों के बावजूद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार दिल्ली का बजट तकरीबन 1 लाख 10 हजार करोड़ का है। रेखा गुप्ता ने दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान कई बड़े ऐलान भी किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए पीडब्ल्यूडी को 5921 करोड़, शहरी विकास के लिए 7887 करोड़, युमानापर के लिए 300 करोड़, झुग्गी के विकास लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़, डेवलपमेंट डिपॉजिट के लिए 914 करोड़ का आवंटन किया गया है। चंद्रवाल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 475 करोड़ का बजट रखा गया। दिल्ली में वॉटर लॉगिंग के समाधान के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया है। 610 करोड़ का बजट वॉटर लॉगिंग से निपटारा पाने के लिए इरिगेशन डिपॉजिट को दिया गया। इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से प्लड प्रोटेक्शन वाल बनाने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग को 12746 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

दिल्लीवासियों को लग सकता है करंट का झटका..... गर्मी में बढ़ सकती है बिजली की दरें



नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर आई है। अप्रैल से बिजली की दरों में बहावरी हो सकती है। दावा है कि ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 38000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बिजली की दरों में बहावरी पर सख्ती देने की भी योजना बना रही है, ताकि उपभोक्ताओं पर इसका असर कम हो। पिछले साल आगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार तीन निजी डिस्कॉम बीआरपीएल, बीबीपीएल और टीपीडीएल को 27200 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) सहित रेगुलेटरी एसेट्स का भुगतान 7 साल के अंदर करे। रेगुलेटरी एसेट्स वे लागतें हैं जिनकी वसूली भविष्य में होने की उम्मीद होती है। आम आदमी पार्टी के शासन के पिछले एक दशक में बिजली की दरों में कोई बहावरी न होने के कारण तेजी से बढ़ी है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने जनवरी में केंद्रीय एजेंसी, अपीलीय बिजली न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) को सूचित किया कि दिल्ली में कुल रेगुलेटरी एसेट्स 38,552 करोड़ रुपये हैं। डीईआरसी की फाइलिंग के मुताबिक बकाया राशि में बीआरपीएल के लिए 19,174 करोड़ रुपये, बीबीपीएल के लिए 12,333 करोड़ और टीपीडीएल के लिए 7,046 करोड़ शामिल हैं। ये राशि डिस्कॉम द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए किए गए अनुमोदित खर्च हैं। वसूली में देरी के कारण ब्याज जमा होने से मूल रेगुलेटरी एसेट्स की राशि बढ़ गई है। शीघ्र अदालत ने डीईआरसी को वसूली योजना तैयार करने, कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) का हिसाब रखने और लागत वसूली में हुई लंबी देरी की व्याख्या करते हुए विस्तृत ऑडिट करने का भी निर्देश दिया था। यह वसूली 7 साल की अवधि में बिजली के बिलों में रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज बढ़कर किए जाने की संभावना है।

हरियाणा में भीषण सड़क दुर्घटना: पिता और तीन मासूम बेटियों की मौत, मां गंभीर घायल

बाइक के परखच्चे उड़ गए और परिवार के सदस्य दूर तक जा गिरे

हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, परिवार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी रिश्तेदारी जा रहा था। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। स हादसे में पिता और उनकी तीन छोटी बेटियों की मौत पर ही मौत हो गई। बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल हुई हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और परिवार के सदस्य सड़क पर दूर तक जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा। पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चरमदीदी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही को उजागर किया है। एक ही मोटरसाइकिल पर पांच लोगों का सवार होना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में वाहन का संतुलन बनाए रखना भी असंभव बना देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हेलमेट पहनना, नियमों का पालन और वाहन की क्षमता के अनुसार ही सवारी करना जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है।



देश के कई राज्यों में गुजराते मार्च में होगी बारिश और बर्फबारी



नई दिल्ली। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश का असर है। राजस्थान में एक हफ्ते से बारिश और तेज हवा का अनुमान है। जो मार्च के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 31 मार्च के बीच राज्य में दो अलग-अलग वेदर सिस्टम सक्रिय होने वाले हैं। मध्यप्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर है। इसके कारण राज्य के उज्जैन, सागर, ग्वालियर-चंबल संभाग में बादल छाए। इसके कारण दिन के तापमान में गिरावट आई। 26-27 मार्च से आंधी-बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित 10 जिलों में बारिश हुई। यहां तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इससे 3-4 दिन तक पूरे प्रदेश में फिर बारिश हो सकती है। 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने की आशंका है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 26 मार्च को मध्य भारत, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में पिछले सप्ताह शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 26 से 31 मार्च के बीच दो अलग-अलग वेदर सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझरू जिलों में बारिश हुई। दोपहर में कोटा, बारां, अजमेर में बारिश हुई।

कोच्चि में हाई-सिक्वोरिटी जोन के ऊपर उड़ाया ड्रोन, दो अमेरिकी हिरासत में



कोच्चि। केरल के कोच्चि में हाई-सिक्वोरिटी जोन के ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन का उपयोग करना एक गंभीर उल्लंघन माना गया है। कैलिफोर्निया (अमेरिका) निवासी केटी मिशेल फेल्ट्स (32) और क्रिस्टोफर रॉस हॉवें (35) को फोर्ट कोच्चि में ड्रोन उड़ाने हुए देखा गया। ये दोनों पर्यटक के तौर पर कोच्चि आए थे। पर्यटन पुलिस ने उन्हें कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) मुख्यालय के पास ड्रोन से वीडियो बनाते हुए पाया, इसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। फोर्ट कोच्चि का यह क्षेत्र रेड जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ किसी भी प्रकार का ड्रोन ऑपरेशन सख्त वर्जित है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने चिल्ड्रन्स पार्क और चैरिटर जंक्शन के पास ड्रोन उड़ाया। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के मुख्य कारण हैं भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। यहां कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ड्रोन के माध्यम से इन संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों के विजुअल भी रिकॉर्ड किए गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), एयरक्राफ्ट एक्ट और ड्रोन रूल्स की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उनके पास से एक ड्रोन और एक लैपटॉप जब्त कर लिया है ताकि डेटा की जांच की जा सके। हालांकि यह मामला गंभीर है, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों को जांच में सहयोग करने और पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस देकर रिहा किया गया है। फोर्ट कोच्चि लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। इस प्रकार की घटनाएं जासूसी या सुरक्षा में संध लाने का जोखिम पैदा करती हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों की सल्लतता ने इस मामले को अधिक चर्चा में ला दिया है।

सऊदी अरब के बीच कुल दस आवागमन होंगे। एयर इंडिया ने कहा कि वह दिल्ली से एक वापसी सेवा और मुंबई से दो सेवाएं संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद और कोझिकोड से एक-एक उड़ान चलाएगी। यह बजट वाहक दिल्ली और मुंबई से मस्कट के लिए चार तय उड़ानें भी चलाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक समूह ने स्लॉट की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यूएई के मार्गों के लिए दस गैर-निर्धारित उड़ानों की घोषणा की। दुबई में वर्तमान में कोई नियमित निर्धारित उड़ानें नहीं हैं, लेकिन दोनों एयरलाइनों द्वारा दिल्ली के लिए तदर्थ सेवाएं जारी हैं। अबू धाबी में केवल एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली, कोझिकोड और मुंबई के लिए तदर्थ उड़ानें संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से रास अल खैमाह, शांजह और अल ऐन के लिए सभी उड़ानें निलंबित हैं। ओमान में मस्कट में नियमित

तमिलनाडु में भूजल स्तर में गिरावट, गर्मियों में मच सकता है पानी के लिए हाहाकार

दिंडीगुल और तिरुपुर जिलों में भूजल स्तर 2.58 मीटर तक गिर गया

चेन्नई।

तमिलनाडु में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। सरकारी जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य भूजल और सतही जल संसाधन डेटा सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 38 में से 29 जिलों में फरवरी में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में भूजल स्तर में गिरावट आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिंडीगुल और तिरुपुर जिलों में भूजल स्तर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जहां दोनों जिलों में भूजल स्तर 2.58 मीटर तक गिर गया है। इसके बाद कोयंबटूर में 2.07 मीटर की गिरावट आई, जबकि सलेम 1.68

मीटर, धर्मपुरी 1.62 मीटर, करूर 1.54 मीटर और पैराम्बलूर 1.20 मीटर में भी भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। इन तीनों गिरावटों से राज्य के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में भूजल भंडारों पर बढ़ते दबाव का संकेत मिलता है। कई अन्य जिलों में भी मामूली गिरावट देखी गई। मदुरै में 1.27 मीटर की गिरावट दर्ज की गई, जबकि विरुधुनगर और परेंबलूर में 1.20 मीटर की गिरावट आई। नमक्कल 1.08 मीटर और इरोड 1.10 मीटर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। उत्तरी तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में 0.99 मीटर और तिरुवनमलाई में 0.85 मीटर की गिरावट दर्ज की गई, जो कई क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर भूस्खलन को



दर्शाती है। इसके विपरीत तटीय और डेल्टा जिलों में अपेक्षाकृत मामूली बदलाव दर्ज किए गए। नागपट्टिनम में सबसे कम गिरावट मात्र 0.03 मीटर दर्ज की गई, इसके बाद नीलगिरि 0.04 मीटर और तिरुवन्नमलाई 0.11 मीटर का स्थान रहा, जो इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत स्थिर भूजल स्थिति का संकेत देता है। जल स्तर में कमी की मात्रा विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि तमिलनाडु

में 2025 में 12 फीसदी ज्यादा वर्षा हुई थी। भारत मौसम विभाग के चेन्नई केंद्र के मुताबिक राज्य में सामान्य 920.9 मिमी के मुकाबले 1,027.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। चेंनालपट्ट एकमात्र ऐसा जिला था जहां सामान्य से कम बारिश हुई, जबकि दस जिलों में सामान्य से 20 से 59 फीसदी ज्यादा बारिश हुई और एक जिले में 60 फीसदी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

एयरलाइन पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए 24 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें चलाएगा

मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया अहम कदम

नई दिल्ली।

मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया गुप ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए अहम कदम उठाया है। एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए 24 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें चलाएगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब क्षेत्र में अस्थिरता के कारण कई हवाई मार्ग निलंबित हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयरलाइन ने बताया कि सेवाएं संयुक्त रूप से एयर इंडिया और उसकी कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएंगी जो मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए अतिरिक्त गैर-निर्धारित सेवाओं के साथ-साथ जेद्दा और मस्कट के लिए नियमित उड़ानें भरेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वाहक जेद्दा के लिए और वहां से अपनी तय उड़ानें संचालित करना जारी रखेंगे, जिससे भारत और

सेवाएं जारी हैं, ज ब फ क सलालाह के लिए सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। सऊदी अरब में, जेद्दा में तय परिचालन सक्रिय है, लेकिन रियाद और दम्मम के लिए सभी उड़ानें निलंबित हैं। बहरीन, दोहा, कुवैत सिटी और तेल अवीव के लिए कोई निर्धारित या तदर्थ सेवाएं नहीं हैं। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य वैश्विक गंतव्यों के लिए एयर इंडिया द्वारा संचालित सभी लंबी दूरी की उड़ानें जारी हैं।

रिपोर्ट में विवरण के मुताबिक निलंबित मार्गों पर बुक किए गए यात्री बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी यात्रा को बाद की तारीख के लिए री-बुक कर सकते हैं या पूर्ण रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं। एयर इंडिया के ग्राहक



आधिकारिक वेबसाइट के जरिए री-बुकिंग या रद्दीकरण के अनुरोध जमा कर सकते हैं या सात दिन 24 घंटे ग्राहक सेवा नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए, जो लोग यूएई से यात्रा कर रहे हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भारत के लिए उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त वाणिज्यिक उड़ान पर री-बुक कर सकते हैं। बयान के मुताबिक एयर इंडिया गुप ने कहा कि वह नियामक मंजूरी और परिचालन की व्यवहार्यता के अधीन, पश्चिम एशिया के लिए और वहां से ज्यादा एड-हॉक उड़ानें संचालित करने के अवसरों का आकलन कर रहा है।

अब सेना में डेढ़ साल में बनेंगे जवान से अफसर, चार साल की नहीं होगी ट्रेनिंग

सेना में अधिकारियों के करीब 8000 से ज्यादा पद खाली

नई दिल्ली।

भारतीय सेना में अब जवान से अफसर बनने का रास्ता आसान हो गया है। खास तौर पर ग्रेजुएट जवानों को इस नए नियम से सीधा फायदा होगा। अब उन्हें अफसर बनने के लिए चार साल की लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, बल्कि सिर्फ डेढ़ साल में ही यह सपना पूरा हो जाएगा। यह बदलाव सेना

की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अफसरों की कमी को पूरा करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना में लंबे समय से अफसरों की कमी है। अधिकारियों के करीब 8000 से जे यादा पद खाली बताए जाते हैं। इससे यूनिट्स की लीडरशिप प्रभावित होती है। यही कारण है कि अब सेना ने अनुभवी जवानों पर भरोसा जताया है। जो जवान पहले से

सेवा में हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्मी कैडेट कोर कॉलेज एंटी में भी बड़ा बदलाव आया है। आर्मी कैडेट कॉलेज एंटी स्कीम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक एसीसी के जरिए अफसर बनने के लिए तीन साल की पढ़ाई और एक साल की ट्रेनिंग होती थी यानी कुल चार साल का समय लगता था। अब ग्रेजुएट जवानों के

लिए यह नियम बदल गया है। उन्हें 3 साल की पढ़ाई नहीं करनी होगी। अब पूरी प्रक्रिया सिर्फ डेढ़ साल में पूरी होगी। हालांकि 12वीं पास जवानों के लिए पुराना नियम जारी रहेगा। इस फैसले से जवानों का करियर तेजी से आगे बढ़ेगा। अनुभवी जवान जल्दी नेतृत्व संभाल सकेंगे और यह बदलाव जवानों का मनोबल भी बढ़ाएगा।



संक्षिप्त समाचार

नेपाल की नदी में दो भारतीय किशोर लापता

पाल्पा, एजेसी। नेपाल के पाल्पा जिले में रविवार को एक नदी में तैरते समय भारत के दो किशोर कथित तौर पर बह गए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले 17 वर्षीय फरान अंसारी और अमन अंसारी तिनाऊ नदी में तैरते समय लापता हो गए। सरकारी दैनिक गोरखापत्र ने पाल्पा जिला पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। ये दोनों किशोर भारत से आए सात युवकों के एक समूह का हिस्सा थे, जो तानसेन नगरपालिका के तिनाऊ नदी तट पर आए थे। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी होम प्रकाश चौधरी ने बताया कि उनमें से दो नदी के बहाव में बह गए। तलाशी अभियान शुरू किया गया लेकिन रविवार शाम तक कोई नहीं मिला। यह नदी नेपाल और भारत के तैराकों के बीच प्रसिद्ध है और कई लोग यहां मनोरंजन के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस नदी में इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

इस्तांबुल में गैस विस्फोट के कारण दो इमारतें ढहने से एक शख्स की मौत

फातिह, एजेसी। इस्तांबुल के मध्य फातिह जिले में प्राकृतिक गैस विस्फोट के कारण रविवार को दो इमारतें ढह गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार खोज और बचाव कर्मियों ने 10 घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। रायपाल वास्तु मूल ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में बचे लोगों का हालचाल पूछा।

वेस्ट बैंक में चार फलस्तीनियों की मौत के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी

वेस्ट बैंक, एजेसी। इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइली बस्तियों में रहने वालों ने शनिवार की रात और रविवार की सुबह कई फलस्तीनी गांवों में उठावा मचाया। इन लोगों ने कारों को तोड़ा, उनमें आग लगाई और कई लोगों को घायल कर दिया। फलस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेसी वाफा ने रविवार को कम से कम छह समुदायों में हुए हमलों की सूचना दी। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि जलूदा गांव में कम से कम तीन फलस्तीनियों को मारपीट से सिर में चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बस्तीवासियों का सामना किया, जिनमें से कुछ घायल हो गए। यह हिंसक घटना उस दिन के एक दिन बाद हुई जब दो गांवों के पास के इलाके में एक फलस्तीनी वाहन से टक्कर में 18 वर्षीय इस्राइली निवासी की मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि वे निवासियों के इस दावे की जांच कर रहे हैं कि टक्कर जानबूझकर की गई थी। गौरतलब है कि इस्राइली सरकार वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बनाने का काम भी आगे बढ़ा रही है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से हिंसा में व्यापक वृद्धि के साथ-साथ बस्तियों में बसने वालों के हमले भी तेज हो गए हैं। इससे पहले अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इस्राइली हमलों में चार फलस्तीनी मारे गए।

हमलों के बीच ईरान का बयान: होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं, पर सुरक्षा नियम सख्त

तेहरान, एजेसी। अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है और इस जलमार्ग में नौवहन जारी है। हालांकि, उसने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाचार एजेसी शिन्हुआ के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमेशा नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा और बचाव का समर्थन किया है। उसने सालों से इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य हमलों के बाद खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय समुद्री सैफ्टी और सिविलियन पर पड़ रहा है। आत्मरक्षा के अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए ईरान ने कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाया है। साथ ही, उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि आक्रमणकारी और उनके समर्थक देश के खिलाफ अपने मकसद को पूरा करने के लिए स्ट्रेट का गलत इस्तेमाल न कर सकें। ईरानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसने आक्रमणकारियों से जुड़े या उनके साथ संबद्ध जहाजों को गुजरने को अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत रोका है। उसने कहा कि दूसरे देशों के या उनसे जुड़े गैर-दुश्मन जहाज, ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बना सकते हैं, बशर्ते उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों में हिस्सा न लिया हो या उनका समर्थन न किया हो, साथ ही बताए गए सैफ्टी और सिविलियन रिगुलेशन का पालन किया हो। मंत्रालय ने कहा कि स्ट्रेट में स्थायी सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए जरूरी है कि ईरान विरोधी सैन्य हमले और धमकियां बंद हों, अमेरिका और इजरायल की अस्थिर करने वाली गतिविधियां रुकें, और ईरान के वैध हितों का पूरा सम्मान किया जाए।

युद्ध के बीच ट्रंप-नेतन्याहू से बोले पहलवी: ईरान इस्लामी गणराज्य नहीं, मौजूदा शासन को उखाड़ फेंके

तेहरान, एजेसी। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने शनिवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान इस्लामिक गणराज्य नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान में मौजूदा शासन को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि वे केवल शासन और दमन करने वाले तंत्र को ही निशाना बनाएं। उन्होंने अनुरोध किया कि आम जनता की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए।

वया बोले रजा पहलवी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में पहलवी ने लिखा कि ईरान का बुनियादी ढांचा वहां के लोगों का है। यह आजाद ईरान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा इस्लामी गणराज्य का ढांचा दमन और आतंक का वह तंत्र है जिसका इस्तेमाल उस भविष्य को साकार होने से रोकने के लिए किया जाता है। ईरान की रक्षा की जानी चाहिए। इस शासन को उखाड़ फेंकना होगा।

पहलवी ने आगे कहा मैं राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से आग्रह करता हूँ कि वे शासन और उसके दमनकारी तंत्र को निशाना बनाया जारी रखें, जबकि ईरानियों को अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक नागरिक ढांचे को बखर्चें दें। अमेरिका और इस्राइल के समर्थन से, और सबसे बढ़कर ईरानी

नाटो प्रमुख ने अमेरिकी हमलों का समर्थन किया, ईरान के खतरे को लेकर चेतावनी दी

वॉशिंगटन, एजेसी। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया और चेतावनी दी कि ईरान ऐसी मिसाइल क्षमताएं विकसित करने के 'बहुत करीब' है जो यूरोप के लिए खतरा बन सकती हैं। उन्होंने यह बयान उस समय दिया जब नाटो हिंद महासागर में स्थित एक अमेरिका-ब्रिटेन सैन्य अड्डे पर लंबी दूरी के हमले की रिपोर्टों का आकलन कर रहा है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने फेस द नेशन पर बोलते हुए कहा कि नाटो अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सका है कि ईरान ने डियागो गार्शिया पर मिसाइल दागी है लेकिन यदि यह सच साबित होता है तो इसके गंभीर निहितार्थ होंगे। उन्होंने कहा, 'हम इस समय इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सच हुआ, तो यह इस बात का और सबूत होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं... वह बेहद महत्वपूर्ण है।' 'रूटे ने कहा कि ईरान प्रमुख यूरोपीय शहरों पर हमला करने की क्षमता के करीब पहुंच रहा है। 'हमें यह निश्चित रूप से पता है कि वे उस क्षमता के बहुत करीब हैं,' उन्होंने ईरानी मिसाइलों की संभावित मारक क्षमता का जिक्र करते हुए कहा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान के पास परमाणु और मिसाइल दोनों क्षमताएं हो गईं, तो यह वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा बन जाएगा। 'अगर ईरान के पास परमाणु क्षमता होती है और वह मिसाइल क्षमता के साथ जुड़ जाती है, तो यह इजराइल, क्षेत्र, यूरोप और वैश्विक स्थिरता के लिए एक सीधा और अस्तित्वगत खतरा होगा,' उन्होंने कहा।

नाटो प्रमुख ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा कि देरी महंगी साबित हो सकती है। उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, 'अगर हम बहुत लंबी बातचीत करते रहे, तो वह समय निकल



सकता है जब इसे रोका जा सकता था।'

उनकी ये टिप्पणियां उस समय आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों की आलोचना की थी कि वे अमेरिकी अभियानों, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं।

रूटे ने इस नाराजगी को स्वीकार किया लेकिन कहा कि अब सहयोगी देशों के बीच समन्वय शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 22 देशों जिनमें नाटो सदस्य और साझेदार जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देश शामिल हैं, ने इस जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की पहल में हिस्सा लिया है।

उन्होंने कहा, 'इन तीन सवालों पर काम हो रहा है-हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कहां चाहिए ताकि जलडमरूमध्य में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।'

रूटे ने यह भी बताया कि सैन्य तैनाती की समयसीमा अभी चर्चा में है और योजनाकार इस पर काम कर रहे हैं। 'सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है-कब,' उन्होंने कहा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी दबाव नाटो की एकता को प्रभावित कर सकता है, तो रूटे ने कहा कि संकट के समय गठबंधन हमेशा एकजुट हुआ है। उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर सहयोग और रक्षा खर्च बढ़ाने के फैसलों का भी उल्लेख किया।

यूक्रेन के मुद्दे पर, उन्होंने अमेरिकी कूटनीति का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और युद्ध के समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है।

'उन्हें इन सभी अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। यूक्रेन युद्ध को सफलतापूर्वक समाप्त करने का उनका प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है,' रूटे ने कहा।

उड़ान के दौरान महिला की मौत, 13 घंटे शव के साथ यात्रा को मजबूर हुए यात्री

लंदन, एजेसी। हांगकांग से लंदन जा रहे ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान में रविवार को एक महिला यात्री की मौत हो गई। उसकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी। महिला के शव को विमान के पीछे हिस्से में रख दिया गया जहां की फर्श गम थी। 13 घंटे से अधिक की उड़ान में शव से बहबू आने लगी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन पायलट ने आपात लैंडिंग कराने के बजाय यात्रा जारी रखी।

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बीए32 के हांगकांग से उड़ान भरने के एक घंटे बाद ही महिला यात्री की मौत हो गई। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एयरबस ए350-1000 में चालक दल के सदस्यों के साथ 331 यात्री सवार थे। महिला की मौत के बावजूद पायलटों ने मार्ग बदलने या हांगकांग लौटने के बजाय हीरो हवाईअड्डे तक यात्रा जारी रखने का फैसला किया। चालक दल के सदस्यों ने पहले शव को शीतलान में रखने पर विचार किया। बाद में शव को पीछे रिसोई घर में ले जाया गया।

लैंडिंग के बाद 45 मिनट पुलिस ने

की विमान की जांच : सूत्र के हवाले से फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया, कर्मचारियों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि रिसोई घर का फर्श गम था। आरोप है कि गर्मी के कारण तीखी गंध उत्पन्न हुई और उड़ान के दौरान केबिन के पिछले हिस्से में फैल गई। कई यात्रियों ने विमान के उस हिस्से से दुर्गंध आने की शिकायत की। लैंडिंग के बाद पुलिस विमान में चढ़ी और सभी यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठे रहने के लिए कहा। लगभग 45 मिनट तक पुलिस ने विमान की जांच की।

यात्री की मौत को नहीं माना जाता चिकित्सा आपातकाल : यात्री की मृत्यु को आमतौर पर चिकित्सा आपातकाल नहीं माना जाता है। शव को आमतौर पर बांडी बैग में रखा जाता है या गर्दन तक कंबल से ढक दिया जाता है। यदि संभव हो तो शव को विमान के किसी कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे कि खाली सीट या किसी अन्य अनुभाग में ले जाने का प्रयास किया जाता है। यदि उड़ान पूरी तरह से भरी हुई है तो शव को उसकी मूल सीट पर वापस रखा जा सकता है।

इस्लामाबाद, एजेसी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच उनके बेटे कासिम खान ने जेल में मुलाकात की है। उनकी सेहत बिगड़ने की खबरों के बीच इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम खान ने सरकार पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था। अब जेल में मुलाकात करने के बाद कासिम खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पिता का संदेश लोगों के सामने रखा है।

इमरान खान का संदेश

कासिम ने इमरान खान का संदेश बताते हुए लिखा, इस देश में जजों को शर्म आनी चाहिए। हम कई बार न्यायपालिका के पास गए लेकिन वे तो अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उन्हें पकता है और अखंडता की कोई परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि वे मुझे नहीं तोड़ सकते थे और इस्लाम मेरी पत्नी को टारगेट करने लगे। इस तरह से आखिर बूराबी बीबी के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे किया जा सकता है। यह सब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है।

शहबाज सरकार ने लगजरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले इंधन पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दी

इस्लामाबाद, एजेसी। पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा संसाधनों से लदे कई वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने हाई-ऑक्टन इंधन की कीमत में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 100 पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लगजरी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले इस इंधन पर टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। बैठक में इंधन कीमतों और आर्थिक राहत से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। इसमें कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनाउल्लाह तरार और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम : रिपोर्ट के अनुसार, हाई-ऑक्टन इंधन की कीमत में इस बढ़ोतरी का असर सार्वजनिक परिवहन और हवाई यात्रा के किराए पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सरकार ने इससे पहले 6 मार्च को भी वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55



रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। यह उछाल अमेरिका-इराकल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण घरेलू ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ने से आया था। उस समय पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपये से बढ़ाकर 321.17 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी, जबकि डीजल की कीमत 280.86 रुपये से बढ़ाकर 335.86 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी।

सरकार पहले भी बढ़ा चुकी है तेल की कीमतें : इस बढ़ोतरी की घोषणा पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। वहीं, 10 मार्च को जेट प्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी किराया बढ़ा दिया था। एयरलाइंस सूत्रों के मुताबिक, घरेलू उड़ानों के टिकट में 2800 से 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई, जो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और अन्य शहरों के लिए लागू है।

इमरान खान से बेटे कासिम ने की जेल में मुलाकात पूर्व पीएम का सुनाया संदेश, कहा जजों को शर्म आनी चाहिए

इमरान खान के हवाले से कासिम ने लिखा, मुझसे 30 मिनट की मुलाकात के लिए उन्हें 24 घंटे आसोलेशन में रहना पड़ता है। किसी भी महिला को नुकसान पहुंचाना इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन उन लोगों का उद्देश्य हमें पता है। जिन जजों पर समाज में न्याय की जिम्मेदारी है, वही गद्दारी कर रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।



बता दें कि इमरान खान के दोनों बेटे लंदन में रहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बेहद कम हो गई है और जेल प्रशासन उनका इलाज भी नहीं करवा रहा है। उन्होंने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि उनका बीजा भी क्लियर नहीं हो रहा है। वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन सरकार को डर है कि इससे दुनिया का ध्यान इमरान खान की ओर चला जाएगा। हालांकि बाद में कासिम खान को पाकिस्तान का बीजा मिल गया और वह जेल में इमरान खान से मुलाकात कर पाए।

बीते दिनों पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शीका अंतरराष्ट्रीय अस्पताल में आंखों के उपचार के लिए स्थानांतरित करने की मांग की थी। खान पिछले साल अक्टूबर से दाहिनी आंख की बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं और उनका उपचार चल रहा है। सरकार के अनुसार, चिकित्सा उपचार के बाद उनकी आंख और दृष्टि दोनों में सुधार हुआ है। 72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और अल कादिर ट्रस्ट भूधराव मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।

न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर विमान और ट्रक की टक्कर

न्यूयॉर्क, एजेसी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग के समय रनवे पर एक फायर ट्रक से टकरा गया। यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल से आ रही थी।



हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ फायरफाइटर और विमान में सवार यात्री घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। हादसे से पहले एयर ट्रेफिक कंट्रोल ने विमान और ग्राउंड वाहन दोनों को रुकने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी टक्कर हो गई।

एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स रोक दी और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात विमान ट्रक से टकराया। हादसे के बाद तुरंत लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। नोटिस के मुताबिक यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट पर सभी विमानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया। अब सवाल है कि आखिर इस सुरक्षित एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा कैसे हो गया। एएफपी की रिपोर्ट के

आखिर कैसे हुआ हादसा ?

अब जांच अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का हादसा कैसे हो गया। जाहिर सी बात है कि रनवे पर फायर ट्रक की मौजूदगी और उधर विमान का लैंड करना एक असामान्य घटना है। अधिकारियों का कहना है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी चूक की वजह से ऐसा हुआ या फिर किसी की लापरवाही की वजह से। एयर कनाडा, एएफए और न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने फिलहाल इस हादसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बता दें कि ला गार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का एक बड़ा एयरपोर्ट है जहां से बड़ी संख्या में घरेलू विमानों का संचालन होता है। इस एयरपोर्ट के कुछ समय के लिए बंद होने से भी हवाई यातायात पर बड़ा फर्क पड़ेगा।

यूएस ने दी ग्लोबल वॉर्निंग, ईरान समर्थक बना सकते हैं अमेरिकियों को निशाना

वाशिंगटन, एजेसी। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगाह किया है कि ईरान समर्थक अमेरिका के नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।



क्या है चेतावनी: अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने लिखा, 'विदेश मंत्रालय दुनिया भर में, और विशेष रूप से मिडल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देता है। विदेश में रह रहे अमेरिकियों को पास के अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा चेतावनियों का पालन करना चाहिए। हवाई क्षेत्र के समय-समय पर बंद होने के कारण यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं।' आगे कहा गया, 'मिडल ईस्ट के बाहर स्थित अमेरिकी राजनयिक केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थक समूह दुनिया भर में अन्य अमेरिकी हितों, ठिकानों या अमेरिकियों को निशाना बना सकते हैं।'

'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में कहा कि इन लक्ष्यों में ईरान की वायुसेना और नौसेना को नष्ट करना, उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता को खत्म करना शामिल है।

बेसंट ने कहा, होर्मुज के किनारे ईरानी किलेबंदी को कमजोर करने के लिए सैन्य संचयनों का उपयोग करने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक वे पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हो जाते। कभी-कभी आपको तनाव कम करने के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है।

तेल की कीमतें बढ़ेंगी : युद्ध के चौथे सप्ताह में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका में नियमित गैसोलिन की औसत कीमत एक महीने पहले की तुलना में 34% अधिक है। यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतें 175 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं।

बेसंट ने कहा कि चलिए मान लेंते हैं कि 50 दिनों तक कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी रहेंगी। लेकिन इसके बदले में 50 वर्षों तक परमाणु हथियार वाले ईरानी शासन का खतरा नहीं रहेगा। कीमतें फिर कम हो जाएंगी। तेल की कीमतें कब तक कम होंगी, इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं पता कि इसमें 50 दिन लगे या सी दिन लगे।

बेसंट ने रविवार को एनबीसी के प्रतिक्रिया दी है। अल जजीरा के अनुसार, कुवैत की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि वहां सुनाई दे रहे धमाकों को आवाजें मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की वजह से आ रही हैं। सेना ने आम लोगों से अपील की है कि वे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।

इसाइली सेना ने बरामद किए टैंक रोधी मिसाइल

दूसरी तरफ, इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है। इस्राइली सेना ने बताया कि उनके सैनिकों ने वहां एक टैंक रोधी मिसाइल पोस्ट और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सेना ने सोशल मीडिया पर इन हथियारों की तस्वीरें भी साझा की हैं।

यूएई पर भी जारी है हमले

ईरान की तरफ से हुए मिसाइल हमलों के बाद इस्राइल के दक्षिणी और मध्य इलाकों में मिसाइलों के टुकड़े गिरने की खबरें मिली हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कई जगहों पर यह मलबा गिरा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का रक्षा मंत्रालय भी ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों और ड्रोंनों का सामना कर रहा है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाजें मिसाइलों को रोकने की वजह से हैं। उनके लड़ाकू विमान और रक्षा प्रणालियां इन खतरों को लगातार नाकाम कर रही हैं।



देशभक्तों के बलिदान से, ईरान की स्वतंत्रता का समय निकट है। ईरान जिंदाबाद!

कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले

इसी बीच, खाड़ी देश कुवैत ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों पर अपनी

